आकाशवाणी
क्षेत्रीय समाचार
देहरादून (उत्तराखण्ड)
शुक्रवार 28.08.2026
समय 07.20

मुख्य समाचार :

- राज्य में संवेदनशील ग्लेशियर झीलों की नियमित वैज्ञानिक निगरानी के साथ अत्याधुनिक अर्ली वार्निंग सिस्टम स्थापित किए जाएंगे।
- उत्तराखंड पुलिस ने स्कूली छात्रों को साइबर अपराध और डिजिटल जोखिमों के प्रति जागरूक करने के लिए राज्यव्यापी वर्चुअल साइबर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया।
- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने युवाओं से शिक्षा के साथ रोजगार, कौशल विकास, नवाचार और उद्यमिता के अवसरों का लाभ उठाकर विकसित उत्तराखंड के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया।
- हल्द्वानी के गौलापार में स्थापित किए जा रहे खेल विश्वविद्यालय के लिए 94 पदों के सृजन को मंजूरी।

ग्लेशियर झीलों की निगरानी

राज्य में संवेदनशील ग्लेशियर झीलों की नियमित वैज्ञानिक निगरानी के साथ अत्याधुनिक अर्ली वार्निंग सिस्टम स्थापित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को जरूरत के अनुसार इनकी संख्या बढ़ाने और संभावित खतरे की स्थिति में समय रहते चेतावनी पहुंचाने की व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। राज्य में 13 ग्लेशियर झीलों को संवेदनशील श्रेणी में चिन्हित किया गया है, जिनमें से चार का सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। शेष झीलों का चरणबद्ध तरीके से वैज्ञानिक सर्वेक्षण किया जाएगा। जल्द ही चमोली की सरस्वती ताल और उत्तरकाशी की केदारताल का भी सर्वेक्षण किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने संवेदनशील झीलों की स्थिति, जलस्तर और आसपास के क्षेत्रों में होने वाले बदलावों का नियमित आकलन करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही आधुनिक सेंसर, जलस्तर मापक उपकरण और संचार प्रणाली के जरिए रियल टाइम निगरानी तथा अर्ली वार्निंग की व्यवस्था विकसित की जाएगी।

इसी क्रम में आपदा प्रबंधन विभाग की राज्य सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष विनय रुहेला और ले. कर्नल रघुवीर सिंह भंडारी (सेवानिवृत्त) ने नेपाल में हुई आपदा के बाद उत्तराखंड में संभावित आपदाओं से निपटने की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारियों के साथ समीक्षा की। उन्होंने जिलाधिकारियों को संवेदनशील क्षेत्रों की नियमित निगरानी और किसी भी असामान्य गतिविधि की सूचना तत्काल देने के निर्देश दिए गए हैं। बांध और बैराज प्रबंधकों के साथ समन्वय तथा पानी छोड़े जाने की स्थिति में निचले क्षेत्रों की आबादी को समय पर अलर्ट करने पर भी जोर दिया गया।

साइबर जागरूकता कार्यक्रम

उत्तराखंड पुलिस ने विद्यार्थियों को साइबर अपराध और डिजिटल जोखिमों के प्रति जागरूक करने के लिए राज्यव्यापी वर्चुअल साइबर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ की उपस्थिति में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रदेश के एक हजार 100 से अधिक राजकीय विद्यालयों के कक्षा छह से 12 तक के करीब एक लाख 75 हजार छात्र–छात्राओं ने हिस्सा लिया।

देहरादून के तपोवन स्थित राजकीय नवोदय विद्यालय के आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम स्टूडियो से संचालित कार्यक्रम में पुलिस महानिदेशक ने विद्यार्थियों से सीधे संवाद किया। उन्होंने ऑनलाइन धोखाधड़ी, सोशल मीडिया सुरक्षा, हैकिंग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबर बुलिंग और साइबर शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया से जुड़े विद्यार्थियों के सवालों के जवाब दिए।

पुलिस महानिदेशक ने विद्यार्थियों से तकनीक का इस्तेमाल ज्ञान, शिक्षा, कौशल विकास और नवाचार के लिए करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए बच्चों और युवाओं का जागरूक होना जरूरी है। उन्होंने विद्यार्थियों से स्वयं साइबर स्मार्ट नागरिक बनने और परिवार तथा मित्रों को भी डिजिटल सुरक्षा के प्रति जागरूक करने को कहा।

मंजूरी

राज्य में वन और जैव विविधता संरक्षण के लिए केंद्र सरकार की ओर से पिछले तीन वर्षों में राष्ट्रीय प्राधिकरण–कैम्पा के तहत 945 करोड़ रुपये के कार्य मंजूर किए गए हैं। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र भेजकर केंद्र के सहयोग और आगामी कार्ययोजना की जानकारी दी।

पत्र के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए राज्य सरकार ने 339 करोड़ रुपये की वार्षिक कार्ययोजना का प्रस्ताव केंद्र को भेजा है। इसके परीक्षण और मूल्यांकन के बाद अब तक 104 करोड़ पैंतीस लाख रुपये मंजूर किए जा चुके हैं।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार के सहयोग के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उत्तराखंड की हिमालयी पारिस्थितिकी, वन संपदा और जैव विविधता का संरक्षण राज्य की प्राथमिकताओं में शामिल है।

रक्षाबंधन

देशभर में आज रक्षाबंधन का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर उनके सुख–समृद्धि और दीर्घायु की कामना कर रही हैं। भाई भी बहनों की रक्षा और सहयोग का संकल्प लेते हैं।

राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने अपने संदेश में रक्षाबंधन को भाई–बहन के पवित्र रिश्ते, स्नेह और विश्वास का प्रतीक बताते हुए कहा कि यह पर्व परिवार के साथ–साथ समाज में प्रेम, सौहार्द और भाईचारे की भावना को मजबूत करता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि रक्षाबंधन भाई–बहन के प्रेम, विश्वास, स्नेह और सुरक्षा के संकल्प का पर्व है। उन्होंने कहा कि यह पर्व नारी सम्मान और सामाजिक सद्भाव की भावना को भी मजबूत करता है। उन्होंने प्रदेशवासियों से महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और सशक्तीकरण के लिए मिलकर कार्य करने का आह्वान किया।

इस बीच, रक्षाबंधन के अवसर पर आज और कल प्रदेश की महिलाओं को उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी गई है।

मुख्यमंत्री युवा विद्यार्थी मंथन

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि विद्यार्थियों के विचार और सुझाव उत्तराखंड के विकास की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने युवाओं से शिक्षा के साथ रोजगार, कौशल विकास, नवाचार और उद्यमिता के अवसरों का लाभ उठाकर विकसित उत्तराखंड के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया।

मुख्यमंत्री कल रुद्रपुर में 'मेरे सपनों का उत्तराखंड' विषय पर आयोजित 'मुख्यमंत्री युवा विद्यार्थी मंथन' कार्यक्रम में विद्यार्थियों से संवाद कर रहे थे। उन्होंने विद्यार्थियों के विचार और सुझाव सुने तथा उनकी जिज्ञासाओं का समाधान किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 'विकसित भारत–विकसित उत्तराखंड' के संकल्प को साकार करने के लिए शिक्षा, रोजगार, नवाचार, कौशल विकास, पर्यटन, कृषि, खेल और तकनीक सहित विभिन्न क्षेत्रों को मजबूत किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि 'मेरे सपनों का उत्तराखंड' अभियान के तहत प्रदेशभर के 2 लाख 67 हजार 744 विद्यार्थियों ने अपने निबंध और विचार भेजे हैं। उन्होंने विद्यार्थियों के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि उनके विचार राज्य के विकास और उज्ज्वल भविष्य के प्रति उनकी सोच को दर्शाते हैं।

खेल विश्वविद्यालय

हल्द्वानी के गौलापार में स्थापित किए जा रहे खेल विश्वविद्यालय के लिए 94 शैक्षणिक, शिक्षणेत्तर, कोचिंग और प्रशासनिक पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है। राज्यपाल की स्वीकृति के बाद शासन ने इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया है।

शासनादेश के अनुसार, खेल विश्वविद्यालय के स्पोर्ट्स कोचिंग विंग में 39 पद सृजित किए गए हैं। इनमें प्रधान कोच और मुख्य कोच, कोच और प्रशिक्षक तथा सहायक कोच और प्रशिक्षक के पद शामिल हैं। अकादमिक और संकाय के लिए 14 पद स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें खेल प्रबंधन और खेल विज्ञान से संबंधित पद शामिल हैं।

खिलाड़ियों की फिटनेस और रिकवरी के लिए खेल चिकित्सक, फिजियोथेरेपिस्ट, खेल मनोवैज्ञानिक, नर्स और वार्ड सहायक समेत 12 पदों को भी मंजूरी दी गई है। इसके अलावा कुलपति, कुलसचिव, उप कुलसचिव, परीक्षा नियंत्रक और वित्त अधिकारी समेत प्रशासनिक और वित्तीय संचालन से जुड़े पद स्वीकृत किए गए हैं। खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि खेल विश्वविद्यालय में खेल विज्ञान, खेल प्रबंधन और आधुनिक कोचिंग की सुविधाएं उपलब्ध होने से प्रदेश के प्रतिभावान खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय की अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं भी चरणबद्ध तरीके से विकसित की जाएंगी।

चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार

उत्तराखंड में सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल और पैरामेडिकल कॉलेज की स्थापना से जुड़े प्रस्तावों को केंद्र सरकार ने विभागीय परीक्षण के लिए भेज दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र भेजकर यह जानकारी दी है।

पत्र के अनुसार, हेमवती नंदन बहुगुणा उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय के अंतर्गत सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल की स्थापना के प्रस्ताव का संबंधित विभाग या प्रभाग द्वारा परीक्षण किया जा रहा है। इसी तरह विश्वविद्यालय के अंतर्गत पैरामेडिकल कॉलेज की स्थापना के प्रस्ताव को भी संबंधित प्रभाग के परीक्षण के लिए भेजा गया है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दोनों संस्थानों की स्थापना के प्रस्ताव केंद्र सरकार के समक्ष रखे थे। राज्य सरकार के अनुसार, सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल की स्थापना से राज्य में उच्चस्तरीय चिकित्सा सुविधाओं को मजबूती मिलेगी, जबकि पैरामेडिकल कॉलेज से प्रशिक्षित पैरामेडिकल मानव संसाधन तैयार करने में मदद मिलेगी।

अनुरोध

प्रदेश के सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने नल जल मित्रों को मनरेगा के माध्यम से अनुमन्य मजदूरी और कार्य दिवस उपलब्ध कराने का अनुरोध किया।

नई दिल्ली के कृषि भवन में हुई मुलाकात के दौरान जल जीवन मिशन से जुड़े विभिन्न विषयों पर दोनो मंत्रियों के बीच चर्चा हुई। इसमें पेयजल परिसंपत्तियों के संचालन और रखरखाव का मुद्दा भी शामिल था।

सतपाल महाराज ने बताया कि नल जल मित्र कार्यक्रम के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर कुशल मानव संसाधन तैयार किया जा रहा है। हालांकि, प्रशिक्षण में ग्रामीण युवाओं और स्थानीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने में परेशानी आ रही है।

उन्होंने बताया कि अधिकांश संभावित प्रतिभागी दैनिक मजदूरी, कृषि और अन्य आजीविका गतिविधियों पर निर्भर हैं। प्रशिक्षण में शामिल होने के दौरान उनकी आय प्रभावित होती है। इसके कारण कई लोग प्रशिक्षण में शामिल नहीं हो पाते।

इसी को देखते हुए महाराज ने पात्र प्रतिभागियों को प्रशिक्षण अवधि में मनरेगा के तहत अनुमन्य मजदूरी और कार्य दिवस उपलब्ध कराने का सुझाव दिया।

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सुझाव पर सहमति जताई। उन्होंने इस संबंध में त्वरित कार्रवाई का आश्वासन दिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा–निर्देश दिए।